

 subahsaverenews@gmail.com
 facebook.com/subahsaverenews
 www.subahsaverenews
 twitter.com/subahsaverenews

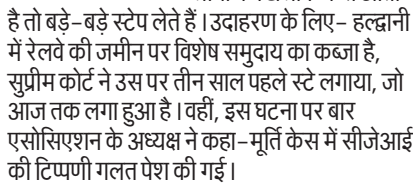
सुप्रभात

धूप निकली दिन सुहाने हो गए
 चाँद के सब रंग फीके हो गए
 इस क़दर रोया हूँ तेरी याद में
 आइने आँखों के धुँधले हो गए
 हम भला चुप रहने वाले थे कहीं
 हाँ मगर हलालत ऐसे हो गए
 तो खुश हो जाएँ अरबाब-ए-हवस
 जैसे वो थे हम भी वैसे हो गए
 हुन्न अब हंगामा-आरा हो तो हो
 इश्क के दावे तो झूठे हो गए
 मुकूत-ए-शाम-ए-गम ये क्या हुआ
 क्या वो सब बीमार अच्छे हो गए
 दल को तेरे गम ने फिर आवाज़ दी
 कब के बिछड़े फिर इकट्ठे हो गए
 ओ 'नासिर' हम भी अपने घर चलें
 बंद इस घर के दरिचे हो गए।
 - नासिर काज़म

जो भी किया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं

सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील
ने रखा अपना पक्ष, कहा- डर भी नहीं है

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर कुमार ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा- सीजेआई के



प्रसंगवशा

भारतीय टैलेंट को अमेरिका से वापस बुलाना इतना मुश्किल क्यों?

निखिल इनामदार

अ मेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एच-1बी वीजा को फ्रीस करके गुना बढ़ाकर एक लाख डॉलर कर दी। कहा जा रहा है कि भारत के पोलिसी मेकर अमेरिका काबिल भारतीयों को वापस अपने देश बुलाने की कोशिश में लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरीबी एक अफसर ने हाल ही में कहा है कि सरकार विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को वापस आने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

वहीं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक सदस्य ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि एच-1बी वीजा हमेशा से मेहनताने के हितों को ही पूरा करता आया है। इसलिए, वीजा फ्रीस में यह बढ़ोतरी भारत के लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि इससे भारत की वैश्वक प्रतिष्ठा को अपने ओर खींचने की क्षमता बढ़ेगी। उन सब बातों का सार यह है कि अब भारत के पास 'रिसर्च ब्रेन ड्रेन' यानी विदेशों में बसे प्रतिभाशाली भारतीयों को वापस लाकर अपने देश में काम करने का माहौल बनाने का अच्छा अवसर है। खासकर टेक्नोलॉजी, चिकित्सा और इनोवेशन से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ में।

हालांकि कुछ उदाहरण बताते हैं कि अमेरिका में सस्ता होती इमिग्रेशन नीतियों के कारण कुछ भारतीय अपने वतन वापस आने पर बिचार कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हजारों लोगों को अमेरिका छोड़कर बेलायत (भारत) लौटने के लिए मनावा आसान नहीं होगा। नितिन हमसन उन कुछ भारतीयों में से एक हैं जो पिछले 20 साल से अमेरिका में बसे हुए थे, लेकिन उन्होंने बड़ा काम उठाते हुए पिछले साल भारत लौटने का फैसला किया।

उनके लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। उन्होंने मेटा में अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़ दी ताकि स्टार्टअप की अनिश्चित दुनिया में कदम रख सकें। हसन ने कहा, 'मैं हमेशा से कुछ अपना शुरू करना चाहता था, लेकिन अमेरिका में मेरी इमिग्रेशन स्थिति ने उस आज़ादी को सीमित कर दिया था।'

भारत लौटने के बाद, हमन ने दो स्टार्टअप शुरू किए हैं, जिनमें से एक है बी2आई (बैक टू इंडिया)। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमेरिका में रहे भारतीयों को वापस लौटने की भावनात्मक, आर्थिक और पेशेवर चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों में आए बदलावों के चलते भारत लौटने की इच्छा रखने वालों की पृष्ठछाछ में तेजी आई है, और एच-1बी वीजा विवाद ने इसे और बढ़ा दिया है।

हसन ने कहा, 'अब कई पेशेवर मान चुके हैं कि उन्हें ग्रीन कार्ड शायद कभी नहीं मिलेगा, और ट्रप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से बी2आई पर आने वाली पूछताछ लगभग तीन गुना बढ़ गई है। सिर्फ पिछले छह महीनों में ही दो सौ से ज्यादा एनआरआई (नॉन-रजिस्टर्ड इंडियन) भारत वापसी के विकल्पों पर चर्चा के लिए हमसे जुड़ चुके हैं।'

अमेरिकी विश्वविद्यालयों से भारतीय प्रतिभा की तलाश करने वाली अन्य कंपनियां भी इस बदलते रूझान की पुष्टि करती हैं। बीडीओ एक्जीक्यूटिव सर्च की सीईओ शिवानी देसाई ने बताया, 'इस सीज़न में आइवी लीगज के विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे माहौल के कारण अमेरिका में काम

कर रहे वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों को अब अपने लंबे करियर को लेकर 'गंभीरता से सोचने' पर मजबूर होना पड़ रहा है।'

देसाइन न कही, हालाँकि उनमें से कई अब भी वहीं टिके हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि शीश पदों पर बैठते-उठते ऐसे अधिकारियों और सीनियर टेक लीडर्स की संख्या बढ़ रही है जो भारत को एक गंभीर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उनके रवैये में यह बदलाव भारत में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े ग्लोबल कैम्पेबिलिटी सेसर्स (जीसीसी) यानी बहुष्ट्रीय कंपनियों के भारत में रिमोटली ऑफिस के कारण भी हो सकता है। ये कंपनियाँ लौटने वाले भारतीयों के लिए बेहतर काम के मौके दे रही हैं।

एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलटन के मुताबिक, अगर अमेरिका टेक प्रोफेशनल्स के लिए अपने दरवाजे बंद करता है, तो ये लोग ऑफशोर ऑपरेशन्स की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में जीसीसी प्रतिभाओं के लिए और भी आकर्षक बनते जा रहे हैं, खासतौर पर तब जब ऑनसाइट अवसर लगातार घट रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मंत्री
सलाहकार और पुस्तक 'सेसेशन ऑफ द सर्वसेफुल
फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया' के लेखक संजय बाबू ने
भी इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा, 'बड़े पैमाने पर
रिस्कें माइग्रेसन यानी प्रतिभाशाली भारतीयों को वापस
लाने के लिए सरकार की ओर से संवर्धित और गंभीर
प्रयास की जरूरत होगी, और वर्तमान में यह कमी है।
सरकार जिन्हें वापस लाना चाहती है इसके लिए सरकार
को सॉफ्टियर से उन वैयक्तिकों की पहचान करनी होगी।
जिनमें उच्च रूप से के वैज्ञानिक, पेशेवर हैं उद्योगी
शामिल हैं। इसके लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है और

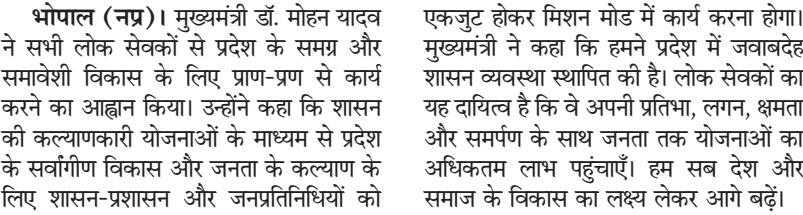
यह पहल सीधे टॉप लेवल से आनी चाहिए।'

उन्होंने कहा कि यही काम भारत को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ताकि अंतरिक्ष और अन्तर्-विश्वीय तत्कनीक जैसे क्षेत्रों में टॉप माइंड्स को वापस लौकर भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान बनाए जा सकें। बारू ने कहा, 'उनमें उद्देश्य और राष्ट्रभक्ति का गहरी भावना थी। अब वापस आने के लिए प्रोत्साहन कहाँ है?' उन्होंने कहा कि इसके कारण, देश में हमेशा से कुछ ऐसे कारनामे रहे हैं जो हुनरमंद पेशेवरों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और भारत ने इस चलन को रोकने के बजाय हमेशा ज़रूर 'मनाया' है। युएन पैकर्स में उन देशों की बड़ती संख्या शामिल है, जो गोल्डन वीजा, नागरिकता या इमिग्रेशन प्रोग्राम के माध्यम से रेजिडेंसी ऑफर कर रहे हैं।

असल में जब अमेरिका ने अपने एनबी वीजा नियमों को कड़ा किया, तभी जर्मनी जैसे देशों ने तुरंत कुराब भारतीय प्रवासियों के लिए अपने दवाजे खोल दिए। पुरा फेक्टर पुरानी और बड़ी समस्या रही है, जैसे कि खराब सकारा निम्प-कानून, थकाने वाली नौकरशाही, और खराब व्यापारिक माहौल। ऐसे ही कुछ कारणों से पिछले कई सालों से अभी और ज्यादा कमजोर वाले भारतीय देश छोड़कर जा रहे हैं। हसन कहते हैं कि अगर सरकार संचर में विश्वों में से भारतीयों को वापस लाने के लिए गंभीर है, तो उन्हें 'कड़ बाधाओं' को एक साथ दूर करने' की दिशा में काम करना होगा। इसमें टेक्स को लेकर आसान कानून, स्पेशल स्टार्टअप वीजा जैसी योजनाएँ और अन्य मौलिक समस्याओं का समाधान शामिल है, जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी और शहरी भीड़भाड़।

मुख्यमंत्री ने किया कलेक्टर-कमिशनर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ

प्रदेश में हमने स्थापित की है जवाबदेह शासन व्यवस्था



एकजुट होकर मिशन मोड में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित की है। लोक सेवकों का यह दायित्व है कि वे अपनी प्रतिभा, लगन, क्षमता और समर्पण के साथ जनता तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाएँ। हम सब देखें और समाज के विकास का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें।

- समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे विकास और कल्याण की किरण- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन का अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण की किरण पहुँचाना है। राज्य सरकार सबके साथ, सबके लिए खड़ी है। जनता में बड़े विश्वास पैदा करना ही सुशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। प्रदेश में जनता का विश्वास हमें मिल रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी पूँजी है और हमें यह जनविश्वास हर हाल में बनाए रखना है।
- योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से मिले जनता को- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इसी बात पर चर्चा किया जाएगा कि शासन व्यवस्था को और अधिक सहज, सरल, बेहतर, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत कैसे बनाया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से जनता तक पहुँच सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिलों में तेजत आधिकारी अपने काम और नवाचार से अपनी पहचान कामरे करे। किसी भी ज्वलंत विषय पर पूरी दक्षता और तथ्यों के साथ अपनी बात रखे। स्थानीय जनता, मीडिया और जनप्रतिनिधियों से निरंतर आदम्य संवाद बनाए रखे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परमत्मा ने यदि हमें समाज के लिए काम करने का दायित्व दिया तो हमें एक विनम्र विद्यार्थी की तरह इस दायित्व का निर्वहन करना ही चाहिए।

गुड गवर्नेंस से ग्रेट रिजल्ट की ओर हों अग्रसर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि लोकतंत्र एवं जनकल्याण में हम सबकी महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट भूमिका है। फोल्ड एवं तेनात अभिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने कहा कि कुछ गुड गवर्नर्स से जनात एंड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हम सबकी को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

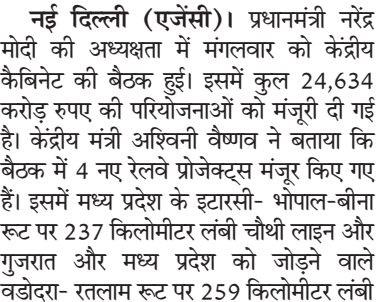
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से विकासित करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के रूप में जन सेवा का मंत्र दिया है। आप सभी इस मंत्र को आत्मसात करते विकासित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को आमिर्ण करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कलेक्टर्स ऐसे जनहितैषी कार्य करें, जो आने

वाले समय में जिले की जनता को याद रहे। अपने कार्यकाल को एक-एक क्षण जितन-कितना में लगाए और प्रदेश को नई ऊँचाईयों में ले जाए। उन्होंने कहा कि नवाचार ऐसे हों, जो विधेयकालिक हों। जिस विभाग से संबंधित नवाचार हों, उसका पूरी कार्ययोजना विभाग से अनुमोदित हो, जिससे वह नवाचार सच हो सके। मुख्यमंत्री की दाल, मसाले एवं टमाटर उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। गेहूँ, मका और मिरच में दूसरे स्थान पर हैं। दुध उत्पादन में हमारा चौथा स्थान है। अब हम विभिन्न प्रयासों से प्रदेश को दुग्ध कैपिटल बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। दुग्ध उत्पादन में हमारा देश में योगदान 9 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत तक ले जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

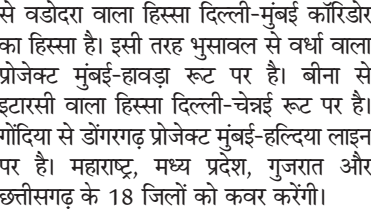
24,634 करोड़ के 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

- **केन्द्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम मोदी थे मौजूद**



तोसरी और गैथी लाइन शामिल है। वैष्णव ने बताया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेगी। भारत के सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेलवे यातायात का 41 फीसदी सभालते हैं, और इन परियोजनाओं से इन कॉरिडोर की क्षमता और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वैष्णव ने कहा कि न प्रोजेक्ट्स से न केवल रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी बल्कि भंडूक होगी, समय की बचत होगी और रेलवे सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार

होगा। उन्होंने कहा, हमने तय किया है कि इन कार्डिओ में कम से कम छह कार्ड लाइन बनेंगी जो कार्डों में संभव होगा, छह लाइनों बनाई जाएंगी। चौथा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना के बीच चौथा लाइन है। यह प्रोजेक्ट 23 नवंबर को शुरू किया जाएगा। वैश्वतनू ने बताया कि आज जिन कार्ड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, वे देश के सात सबसे व्यस्त रेलवे स्टूट्स का हिस्सा हैं। देश का 41 फीसदी कार्गो और 41 फीसदी ट्रेफिक पैसेंजर ट्रेफिक इन स्टूट्स से गुजरता है। रेलमंत्रालय



किसानों को हर हाल में मिलेगा सोयाबीन फसल का उचित दाम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की मेहनत का सम्मान दिलाने के लिए उन्हें हर हाल में सोयाबीन फसल का उचित दाम

